तापमान

भोपाल	34.9°	20.4°
इंदौर	33.7°	21.5°
जबलपुर	38.3°	19.5°
ग्वालियर	35.0°	24.1°

दैनिक नईदुनिया

भोपाल एवं सागर से एकसाथ प्रकाशित

वर्ष- 78
(भोपाल : वर्ष 40 अंक 119, पृष्ठ 12)
शनिवार 29 मार्च 2025
राजधानी संस्करण
कीमतः 3:00 रुपये

राजधानी... कर्मयोगी भाव, भावनाओं के साथ प्रतिबद्ध...

खेल... मुंबई सिटी के कोच पेट्र क्राटकी ने प्लेऑफ मुकाबले से...

व्यापार... टेलीकॉम कंपनियों ने सोर्स कोड शेयर करने की शर्त...

देश-विदेश... थाईलैंड और म्यांमार में भूकंप से इमारतें...

www.naiduniaonline.com

राणा सांगा का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तानः रविशंकर

नईदिल्ली(एजेंसी)। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने राणा सांगा को लेकर एक राज्यसभा सदस्य के बयान पर उठे विवाद का मुद्दा शुक्रवार को लोकसभा में उठाया और कहा कि राणा सांगा जैसे महान सपूतों का अपमान देश नहीं सहेगा।

सदन में शून्यकाल के दौरान पहले भाजपा सांसद राव राजेंद्र सिंह ने यह विषय उठाया। इसके बाद प्रसाद ने भी राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन के बयान की निंदा की। प्रसाद ने कहा, ''राणा सांगा भारत की विरासत हैं। उनका त्याग और बलिदान हम सभी लोगों को गौरवान्वित करता है। वह हमारे देश की प्रेरणा हैं। उनके बारे में हल्की बातें की गई हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। भाजपा नेता ने कहा, ''चाहे शिवाजी हों, राणा सांगा हों, उनका अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान।'' राव राजेंद्र सिंह ने कहा, ''राजस्थान के योद्धा को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसकी मैं निंदा करता हूं। प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूं कि क्या वह इस तरह के कथन (शेष पेज 2 पर)

लोकसभा से माल परिवहन विधेयक पारित...

दोनों सदनों की कार्यवाही एक अप्रैल तक स्थगित

नईदिल्ली(एजेंसी)। संसद का बजट सत्र अपने आखिरी सप्ताह में प्रवेश कर गया है। संसद सत्र के दौरान काफी हंगामा देखने को मिला। आज दोनों सदनों में कई मुद्दों पर चर्चा की है, जिसके बाद दोनों सदन एक अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं।

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 1 अप्रैल, मंगलवार, सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में सांसदों के निजी तौर पर लाए गए गैर-सरकारी संकल्पों पर चर्चा हुई। सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार के दिन का कुछ समय गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर विचार किया जाता है। लोकसभा में देश में हवाई किराये को विनियमित करने के लिए उचित उपाय सुनिश्चित करने के लिए सांसद शफी परम्बिल द्वारा लाए गए संकल्प पर चर्चा हुई। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 लोकसभा में पेश कर दिया गया है। पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने यह विधेयक पेश किया। भारतीय बंदरगाह विधेयक का उद्देश्य बंदरगाहों से संबंधित कानूनों को मजबूत करना और एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देना है। साथ ही व्यापार में सुगमता लाना और भारत की तटीय रेखा का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना है। इस विधेयक में मेरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल को गठित करने का भी प्रावधान है, जिससे बंदरगाह क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा।

राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ व्यापार सलाहकार समिति की बैठक से शुक्रवार को नाराज होकर चले गए। वे बैठक में शिष्टाचार की कमी से नाराज थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बैठक में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच नकली वोटर आईडी नंबर्स के मुद्दे पर चर्चा के लिए मतभेद थे, इससे भी राज्यसभा सभापति नाराज थे। भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने नए आप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025 पर कहा, बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में अगर यहां की जनसांख्यिकी को बदलने का काम कर रहे हैं। वे भारत को कमजोर कर रहे हैं लेकिन भारत की सरकार सक्रिय है उन्हें रोकने के लिए। बंगाल की सरकार कई स्थानों पर कैंप चलाती है जहां पर बांग्लादेशी आते हैं और वहां से उन्हें दूसरी जगहों पर भेजा जाता है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि झारखंड की आदिवासी आबादी भी इससे परेशान है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के संसद में दिए गए बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि साफ संकेत हैं कि हम पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए चिंतित हैं। ये परेशानी है कि हमारी पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत बंद है, वरना हम पाकिस्तान की सरकार के सामने इस मुद्दे को उठा सकते थे। विदेश मंत्री ने जो बातें कही वो सही हैं और हमें पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की चिंताजनक हालत पर संज्ञान लेना चाहिए। पंजाब में कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाथ के साथ मारपीट मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। भाजपा सांसद नवीन जिंदल ने शुक्रवार को लोकसभा में सीबीआई जांच की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि मैंने सदन में ये मुद्दा उठाया। 13 मार्च को पंजाब में एक कर्नल को 12 पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से पीटा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले में सीबीआई जांच के आदेश देने चाहिए। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, राणा सांगा संपूर्ण भारतवर्ष के लिए स्वतंत्रता संघर्ष के प्रतीक हैं।

मुश्किल वक्त में जरूरतमंद के आंसू पोंछती है और सहारा बनती है संबल योजना

भोपाल(काप्र)।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के अलावा भी ऐसी जरूरतें होती हैं, जिनके लिए पैसा जरूरी होता है। प्रसूति, बीमारी, दिव्यांगता और किसी अपने को खो देने जैसे मुश्किल समय में कई बार हम स्वयं को असहाय महसूस करते हैं। संबल योजना ऐसे ही मुश्किल वक्त में जरूरतमंद के आंसू पोछती है और उनको सहारा प्रदान करती है।

राज्य सरकार प्रदेश के गरीब और श्रमिक वर्ग के कल्याण तथा उनका भाग्य बदलने के लिए दृढ़ संकल्पों के साथ कार्य कर रही है। डॉ. यादव मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत प्रदेश के 23 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों के खातों में 550 करोड़ रूपए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित करने के बाद परिवारों को मंत्रालय से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पांच हितग्राहियों से वर्चुअली बातचीत कर उनके परिजन के अवसान पर संवेदनाएं प्रकट की। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल वर्चुअली शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों, नगर निगमों, नगर परिषद और ग्राम पंचायतों के हितग्राही और जनप्रतिनिधि भी वर्चुअली जुड़े। मुख्यमंत्री का पौधा भेंटकर स्वागत किया गया।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के श्रमिक परिवारों का अभिवादन करते हुए कहा कि परिश्रम से अपने और अपने परिवार का जीवन चलाने वाले श्रमिक ही प्रदेश के विकास की नींव हैं। परिश्रम से ही हमारी प्रतिभा निखरती है और आने वाली पीढ़ी के सुखद भविष्य का मार्ग भी बनता है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से जुड़े संबल योजना के हितग्राहियों से वर्चुअली चर्चा की। इस क्रम में उन्होंने मंदसौर की श्रीमती अंजली रैकवार, खरगोन की श्रीमती प्रेमलता कर्मा, शहडोल की श्रीमती मन्नू ढीमर, दतिया की श्रीमती कल्लन वाल्मीक, सीहोर की श्रीमती शिव कुमारी से (शेष पेज 2 पर)

जरूरतमंदों की जरूरत के समय मदद करती है : पटेल

श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना वर्ष 2018 में प्रारंभ हुई थी। सरकार की यह योजना जरूरतमंदों की मदद करने वाली योजना है। योजना के प्रारंभ से अब तक 5 हजार 927 करोड़ रुपए का लाभ हितग्राहियों को मिल चुका है। श्री पटेल ने कहा कि आज 23 हजार 162 प्रकरणों में श्रमिक परिवारों को 505 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मार्गदर्शन में योजना का बैकलॉग खत्म किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में कई जिले ऐसे हैं जहां हितग्राहियों को 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि औसतन प्रति माह 3.5 हजार प्रकरणों का निराकरण संबल योजना के तहत किया जाता है।

खास-खबर

हवाई अड्डों पर निःशुल्क पेयजल के लिए वाटर कूलर की व्यवस्था की जाएः बिरला

नईदिल्ली(एजेंसी)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से कहा कि वह हवाई अड्डों पर वाटर कूलर की व्यवस्था करें, ताकि यात्रियों को निशुल्क पेयजल उपलब्ध हो सके।

सदन में गैर-सरकारी कामकाज के तहत कांग्रेस सांसद शफी परम्बिल के 'देश में हवाई यात्रा किराये के विनियमन के लिए उचित उपाय' संबंधी निजी संकल्प पर चर्चा के दौरान बिरला ने यह टिप्पणी की।

बिहार को मोदी सरकार का तोहफा, कई परियोजनाओं को मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी

नईदिल्ली(एजेंसी)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइब्रिड एन्युटी मोड पर बिहार में 4-लेन ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर (हा-119) (120.10 किमी) के निर्माण को मंजूरी दी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना पटना-आरा-सासाराम को जोड़ेगी। यह परियोजना पांच राष्ट्रीय राजमार्गों और चार राज्य राजमार्गों को जोड़ेगी। इससे बिहार में भीड़भाड़ काफी कम हो जाएगी। अश्विनी वैष्णव ने आगे बताया कि कोसी नदी पूरे बिहार राज्य में बहने वाले पानी का एक प्रमुख स्रोत है और कोसी नदी के पानी को मेची नदी से जोड़ने के लिए 6,282 करोड़ रुपये की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि यह परियोजना भारी आर्थिक लाभ और महत्वपूर्ण आपदा प्रबंधन प्रदान करेगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में पीएंडके उर्वरकों पर सस्ती, रियायती और उचित दरें सुनिश्चित करने के लिए खरीफ 2025 के लिए 37,216.15 करोड़ रुपये की एनबीएस सब्सिडी को मंजूरी दी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा सुनिश्चित किया है कि किसानों पर (शेष पेज 2 पर)

मोदी कल से महाराष्ट्र-छग के दौरे पर

नईदिल्ली(एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के एकदिवसीय के दौरे पर होंगे और इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ कुछ विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कुछ परियोजनाओं के परिचालन का शुभारंभ करेंगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक श्री मोदी महाराष्ट्र में नागपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वह वहां स्मृति मंदिर में दर्शन करेंगे तथा दीक्षाभूमि भी जाएंगे तथा डॉ. बी. आर. अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखेंगे, सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड में यूएवी (मानव रहित सैन्य वायुयान) के माध्याम से छोड़े जाने वाले उड़ने वाले विशेष बमों के परीक्षण स्थल और हवाई पट्टी (लोइटरिंग म्यूनिशन टेस्टिंग रेंज एंड रनवे) का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी इस दौरे में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित 33,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की (शेष पेज 2 पर)

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 62 करोड़ लोग कवर

नयी दिल्ली(एजेंसी)। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे पी नड्डा ने शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि सरकार ने एबी-पीएमजेएवाई के तहत देश के 62 करोड़ लोगों को कवर किया है, जिसके तहत प्रति वर्ष एक परिवार को पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है।

स्पेशल खबर *आरबीआई ने दी मंजूरी, बढ़ेगा इंटरचेंज शुल्क...*

एटीएम से पैसे निकालना होगा महंगा

नईदिल्ली(एजेंसी)।

भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम से पैसे निकालने पर इंटरचेंज शुल्क में वृद्धि की घोषणा की है, जिससे 1 मई से नकद निकासी महंगी हो जाएगी। इस बदलाव का असर अक्सर एटीएम का इस्तेमाल करने वालों पर पड़ेगा, जिससे पैसे निकालने की लागत बढ़ जाएगी।

आरबीआई ने बताया कि एक मई से मुफ्त मासिक लेनदेन के बाद एटीएम से पैसे निकालने पर दो रुपये से लेकर 23 रुपये तक का शुल्क लगेगा। एटीएम इंटरचेंज शुल्क वह राशि है जो एक बैंक दूसरे बैंक को एटीएम लेनदेन की सुविधा के लिए देता है। बैंक आमतौर पर इस लागत को ग्राहकों पर डाल देते हैं।

अगर एचडीएफसी बैंक का कोई ग्राहक दिल्ली में एसबीआई एटीएम से पैसे निकालता है, तो एचडीएफसी बैंक महीने में एसबीआई एटीएम से तीसरे लेनदेन के बाद शुल्क ले सकता है। शुल्क में संशोधन व्हाइट-लेबल एटीएम ऑपरेटरों के अनुरोध के बाद किया गया है, जिन्होंने अपने व्यवसाय को प्रभावित करने वाली परिचालन लागत में वृद्धि के कारण उच्च निकासी शुल्क की मांग की थी। छोटे बैंकों के ग्राहक, जो एटीएम सेवाओं के लिए बड़े वित्तीय संस्थानों पर निर्भर हैं, सबसे अधिक प्रभावित होने की आशंका है। 10 अक्टूबर 2014 को जारी आरबीआई के परिपत्र के अनुसार, मेट्रो शहरों (मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद) के ग्राहक अन्य बैंकों के एटीएम से हर महीने तीन मुफ्त एटीएम लेनदेन के हकदार हैं। गैर-मेट्रो स्थानों में, यह सीमा प्रति माह पाँच मुफ्त लेनदेन ही रहती है। बैंक ग्राहकों को अक्सर तकनीकी त्रुटियों के कारण एटीएम लेनदेन में असफलता का सामना (शेष पेज 2 पर)

म्यूचुअल फ़ंड निवेश बाज़ार के जोखिमों के अधीन हैं, योजना से जुड़े सभी दस्तावेज़ों को ध्यान से पढ़ें.